

सुरेश धस पीछे पड़ जाएं तो काम हो जाता है, मुख्यमंत्री फडणवीस

देविंद्र जी कि भुमिका जनता को पसंद हैं।



दैनिक भारत कि तामीर

संपादक - काज़ी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com



मेरी रगों में गोपीनाथ मुंडे का खून है, जिनकी करनी और कथनी एक थी , पंकजा मुंडे।

बीड। (तामीर न्यूज़) जिले के मस्साजोग के सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड को लेकर भाजपा विधायक सुरेश धस लगातार सक्रिय हैं। उन्होंने हत्या के आरोपियों को सजा दिलाने के लिए कई मोर्चे निकाले और इस मामले में मंत्री धनंजय मुंडे को भी निशाने पर लिया। इससे राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेताओं ने उनकी आलोचना की और उन्हें रोकने की मांग की।

लेकिन अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक कार्यक्रम में सुरेश धस की खुलकर तारीफ की है। फडणवीस ने कहा कि सुरेश धस आधुनिक भगीरथ हैं।

फडणवीस ने कहा - सुरेश धस के पीछे पड़ने से काम हो जाता है

बीड जिले के आष्टी विधानसभा क्षेत्र में 'खुंटेफळ जलाशय परियोजना' का लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों संपन्न हुआ। इस मौके पर विधायक सुरेश

धास, सांसद बजरंग सोनावणे और मंत्री पंकजा मुंडे भी मौजूद थीं। इस दौरान मुख्यमंत्री फडणवीस ने सुरेश धस की जमकर सराहना की और कहा,

इस प्रोजेक्ट को २०२२ में हमारी सरकार ने मंजूरी दी थी। इस पर ११,००० करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। कारण? क्योंकि सुरेश धस जब किसी मुद्दे के पीछे पड़ जाते हैं, तो वो सिर खा जाते हैं। यह शब्द भले ही सही न लगे, लेकिन उनकी जिद के कारण यह प्रोजेक्ट तेज गति से आगे बढ़ रहा है। अब धाराशिव और आष्टी तालुका में बड़ी मात्रा में पानी पहुंचेगा, जिससे इस क्षेत्र का सूखा बीते दिनों की बात हो जाएगी और यह इलाका हराभरा हो जाएगा।

मराठवाड़े को स्थायी रूप से सूखा मुक्त करना जरूरी - फडणवीस

मुख्यमंत्री ने कहा, २०१४-१५ में जब भयंकर सूखा पड़ा था, तब हमारी सरकार ने 'जलयुक्त शिवार योजना' शुरू की थी। इस योजना के कारण कई गांवों में पानी आया। उच्च न्यायालय की समिति ने भी पहली बार स्वीकार किया कि जल स्तर बढ़ा है। लेकिन मराठवाड़े को स्थायी रूप से सूखा मुक्त करना है, तो जल संरक्षण के साथ-साथ पश्चिम की ओर बहने वाले पानी को गोदावरी घाटी में लाना जरूरी है। जब तक यह पानी गोदावरी घाटी में नहीं आएगा, तब तक मराठवाड़ा पूरी तरह सूखा मुक्त नहीं हो सकता।

मुख्यमंत्री की सख्त भूमिका जनता को पसंद आई - सुरेश धस

विधायक सुरेश धस ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कड़ी कार्रवाई के लिए प्रशंसा करते हुए कहा,

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, आपने संतोष देशमुख हत्याकांड में जो कड़ा रुख अपनाया है, वह जनता को बेहद पसंद

आया है। आपने कहा है कि इस मामले के आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा, इस पर जनता को पूरा विश्वास है।

संतोष देशमुख हत्याकांड में सख्त कार्रवाई होगी - फडणवीस

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि संतोष देशमुख हत्याकांड के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी।

ऐसी घटनाओं को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे कोई भी हो, हर दोषी पर कार्रवाई होगी। मैं बीड की जनता से अपील करता हूं कि हम सब छत्रपति शिवाजी महाराज के मावले हैं। उन्होंने सभी १८ पगड जातियों को एक साथ लाकर स्वराज्य की स्थापना की थी। हमें भी एक होकर नया बीड बनाना है। बीड ने बहुत बड़े नेता दिए हैं, और यह परंपरा आगे भी जारी रहेगी। मैं आप सभी के प्रयासों के साथ खड़ा हूं, यह मैं आपको आश्वासन देता हूं।

मुख्यमंत्री साहेब देखिए... राष्ट्रवादी के सांसद के नाम पर भी भाजपा कार्यकर्ताओं की ज्यादा तालियां बज रही हैं - पंकजा मुंडे

इस दौरान मंत्री पंकजा मुंडे ने मंच से सभी नेताओं का नाम लेते हुए बीड के सांसद बजरंग सोनावणे का जिक्र किया और कहा,

मेरा चुनाव हराकर जो बीड के सांसद बने हैं, वह हैं बजरंग बाप्पा।

इसके बाद सभा में जोरदार तालियां और सीटियां बजने लगीं। फिर जब पंकजा मुंडे ने विधायक सुरेश धस का नाम लिया, तो उन्होंने मुख्यमंत्री फडणवीस की ओर इशारा करते हुए मजाकिया लहजे में कहा,

मुख्यमंत्री साहेब देखिए... राष्ट्रवादी के सांसद के नाम पर भी भाजपा के कार्यकर्ताओं की तालियां ज्यादा बज रही हैं।

बोलना और करना अलग-अलग, यह मेरे खून में नहीं - पंकजा मुंडे का जवाब सुरेश धस को

विधायक सुरेश धस ने पहले पंकजा मुंडे पर आरोप लगाया था कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में अपक्ष उम्मीदवार भीमराव धोंडे की मदद की थी। अब तक पंकजा मुंडे ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन इस कार्यक्रम में उन्होंने जवाब देते हुए कहा, मेरा वचन ही मेरा शासन है, यह कहते हुए उन्होंने बाहुबली फिल्म का डायलॉग मारा और कहा, मैं गोपीनाथ मुंडे की बेटी हूं। बोलना एक और करना कुछ और - यह मेरे खून में नहीं है। इस जवाब से साफ हो गया कि पंकजा मुंडे ने अब खुलकर सुरेश धस के आरोपों का जवाब देना शुरू कर दिया है।

अल्पसंख्यक समाज की समग्र प्रगति के लिए योजनाओं और उपक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन करें

मंत्री दत्तात्रेय भरणे के निर्देश

मुंबई (विशेष प्रतिनिधि): राज्य में अल्पसंख्यक समाज की समग्र प्रगति के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं। इन योजनाओं का लाभ इस समुदाय के पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए सख्त और सुव्यवस्थित योजना बनाएं, ऐसे निर्देश अल्पसंख्यक विकास मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने बुधवार को दिए।

अल्पसंख्यक विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक मंत्रालय में उनकी अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में विभाग के सचिव रुचेश जयवंशी, राज्य के विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी, जिला योजना अधिकारी (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से), उपसचिव मिलिंद शेणॉय और श्रीमती विशाखा आढाव उपस्थित थे।

मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज के लिए चलाई जा रही योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए और जनहितकारी उपक्रमों को बढ़ावा दिया जाए। इस समाज की समग्र प्रगति के लिए निधि की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। समाज को मुख्यधारा में लाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे और सरकार उनकी संपूर्ण प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने आगे कहा कि अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना, मौलाना आज़ाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल का निधि बढ़ाने के लिए प्रयास, स्वयं सहायता बचत समूह योजना और स्कूल आधुनिकीकरण जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को और प्रभावी तरीके से लागू किया जाए। इन सभी लोककल्याणकारी योजनाओं का लाभ योग्य लाभार्थियों तक पहुंचना चाहिए, इसके लिए अधिकारी सुनिश्चित करें, ऐसा निर्देश उन्होंने बैठक में दिया।

कानून और व्यवस्था बहाल करें और उजनी का पानी बीड को दें

सांसद बजरंग सोनावणे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से पत्र के माध्यम से की मांग

बीड: बीड जिले में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ चुकी है, इसे फिर से बहाल किया जाए। साथ ही, बीड जिले के किसानों के जीवन में हरित क्रांति लाने के लिए उजनी बांध से १० टीएमसी पानी बीड जिले के लिए विशेष रूप से मंजूर किया जाए। यह मांग सांसद बजरंग सोनावणे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से खुंटेफळ (ता. आष्टी) में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ज्ञापन के माध्यम से की।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंपे गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि बीते कुछ वर्षों में बीड जिले में कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहद चिंताजनक बन गई है। अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण पुलिस विभाग स्वतंत्र और प्रभावी रूप से कार्य करने में असमर्थ हो रहा है। स्थानीय स्तर पर पुलिस प्रशासन पर अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है, जिससे कानून

के प्रभावी क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसी कारण जिले में अन्य अवैध गतिविधियों के साथ-साथ अपहरण, फिरौती, उत्पीड़न, हत्या और अन्य गंभीर अपराधों की संख्या बढ़ रही है। नागरिकों में पुलिस बल के प्रति अविश्वास की भावना पैदा हो गई है, और कानून-व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। जिले में नए उद्योग लगाने को लेकर उद्यमियों में भी निरुसाह देखने को मिल रहा है, जिसे बदलावा आवश्यक है।

वहीं, बीड जिला हमेशा से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में शामिल रहा है। औसत वर्षा कम होने के कारण जिले की अधिकांश कृषि भूमि अक्षिप्त है। नतीजतन, किसान कठिनाई में हैं और बड़ी संख्या में रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। ऐसे में अगर सिंचाई सुविधाएं बढ़ाई जाएं तो पलायन रुकेगा, कृषि उत्पादन बढ़ेगा और बेरोजगारी भी कम होगी।

बीड के लिए उजनी बांध से १० टीएमसी पानी मंजूर करने की मांग

वर्तमान में उजनी बांध से अतिरिक्त पानी नदी के रास्ते बह जाता है। यदि इसमें से १० टीएमसी पानी बीड जिले के लिए विशेष रूप से मंजूर किया जाए, तो इसे सीना नदी के माध्यम से लिफ्ट करके सीना-कोळेगाव परियोजना, फिर अपर मांजरा परियोजना और अंत में मांजसुंबा घाटमाथा तक ले जाया जा सकता है। इस तरह पाटोदा, बीड, केज, धारूर और अंबाजोगाई तालुकों के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में प्राकृतिक जल प्रवाह से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। इसके लिए इस योजना

की तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता की तुरंत जांच करने के आदेश दिए जाएं और बीड जिले के लिए विशेष रूप से १० टीएमसी पानी मंजूर किया जाए। साथ ही, इस परियोजना के लिए आवश्यक धनराशि और स्वीकृति को प्राथमिकता दी जाए, ऐसी मांग की गई है।

कानून और व्यवस्था सुधारने के लिए आवश्यक कदम बीड जिले की पुलिस को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त किया जाए ताकि वे निष्पक्ष और कानून के अनुसार कार्य कर सकें।

कानून और व्यवस्था बनाए रखने में बाधा उत्पन्न करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को तुरंत जिले से बाहर स्थानांतरित किया जाए।

जिले में अपराध नियंत्रण के लिए एक स्वतंत्र जांच समिति गठित कर आवश्यक सुधार सुझाए जाएं।

दिल्ली में खुलेगा असदुद्दीन ओवैसी का खाता? एंजिट पोल के आंकड़ों में साफ हुई तस्वीर

नवी दिल्ली: संवादाता

दिल्ली विधानसभा चुनाव में कई क्षेत्रीय पार्टियां भी अपना दांव आजमा रही हैं। इनमें मायावती की बसपा, अजित पवार की एनसीपी, चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम शामिल है। इसके अलावा वामपंथी दल भी कुछ सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। एंजिट पोल के सर्वे में इन पार्टियों की क्या स्थिति है? क्या ये खाता खोल पाएंगे या बीते चुनाव की तरह इन्हें मायूसी हाथ लगी रही है।

पोल डायरी और टाइम्स नाउ जेवीसी सर्वे के अलावा कोई भी अन्य के खाते में सीट जाते हुए नहीं दिखा रहा। ऐसे में चाहे मायावती हों या

अजित पवार, असदुद्दीन ओवैसी हों या फिर चंद्रशेखर आजाद किसी की भी पार्टी यहां खाता

खोलती नहीं दिख रही। ना ही वाम दलों को कोई सीट जाती दिख रही है। अगर अन्य के खाते में कोई सीट नहीं जाती तो यह ओवैसी के लिए बड़ा झटका होगा क्योंकि उन्होंने दिल्ली



में अगर सिंचाई सुविधाएं बढ़ाई जाएं तो पलायन रुकेगा, कृषि उत्पादन बढ़ेगा और बेरोजगारी भी कम होगी।

बीड के लिए उजनी बांध से १० टीएमसी पानी मंजूर करने की मांग

वर्तमान में उजनी बांध से अतिरिक्त पानी नदी के रास्ते बह जाता है। यदि इसमें से १० टीएमसी पानी बीड जिले के लिए विशेष रूप से मंजूर किया जाए, तो इसे सीना नदी के माध्यम से लिफ्ट करके सीना-कोळेगाव परियोजना, फिर अपर मांजरा परियोजना और अंत में मांजसुंबा घाटमाथा तक ले जाया जा सकता है। इस तरह पाटोदा, बीड, केज, धारूर और अंबाजोगाई तालुकों के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में प्राकृतिक जल प्रवाह से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। इसके लिए इस योजना



आज बीड में पहली बार तेज रेलगाड़ी का सफल परीक्षण हुआ। इसके लिए पुणे रेलवे विभाग के यातायात सुरक्षा आयुक्त और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी रेलवे ट्रैक और स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान, बीड शहर के बार्शी नाका क्षेत्र में रेलवे स्टेशन की मांग को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) पदवीधर संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रो. अमर शेख और रेलवे क्रियान्वयन समिति के पदाधिकारी खुर्शीद आलम सहित अन्य पदाधिकारी अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए दिखाई दिए।

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

रेलवे पुलों का मुद्दा विधायक संदीप क्षीरसागर ने रेलवे सुरक्षा आयुक्त के सामने रखा

बीड निर्वाचन क्षेत्र में पुल न होने से यातायात में परेशानी



बीड, ५ फरवरी (प्रतिनिधि): बीड निर्वाचन क्षेत्र के कुछ स्थानों पर रेलवे पुल न होने के कारण यातायात में कठिनाई हो रही है। इस विषय को लेकर विधायक संदीप क्षीरसागर पिछले कई दिनों से लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच, बुधवार (५ फरवरी) को बीड रेलवे की हाई-स्पीड

टेस्ट के लिए रेलवे सुरक्षा आयुक्त मनोज अरेरा आए थे, उस दौरान विधायक संदीप क्षीरसागर ने यह मुद्दा उनके सामने उठाया।

बीड निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत शिरूर कासार तहसील के हिवरसिंगा, बरगावाडी, जबळगिरी और बीड तहसील के चरहाटा में जाने के लिए रेलवे पुल का निर्माण नहीं

किया गया है। इससे इन गांवों में यातायात की गंभीर समस्या बनी हुई है। इस विषय पर विधायक संदीप क्षीरसागर लगातार प्रशासन और सरकार के समक्ष अपनी मांग रख रहे हैं। उन्होंने कई बार पत्राचार किया है और अधिकारियों के साथ बैठकें भी की हैं।

इस दौरान, अहमदनगर-बीड-परली रेलवे मार्ग की हाई-स्पीड टेस्टिंग के लिए पुणे डिवीजन के रेलवे यातायात सुरक्षा आयुक्त मनोज अरेरा सहित रेलवे प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर विधायक संदीप क्षीरसागर ने अधिकारियों से मुलाकात कर रेलवे पुलों के निर्माण का मुद्दा उठाया और रेलवे विभाग से इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर जल्द समाधान निकालने की मांग की।

इस मौके पर सांसद बजरंग सोनवणे, पूर्व विधायक सैयद सलीम, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरदचंद्र पवार गुट के जिला अध्यक्ष राजेंद्र मस्के, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट) के जिला अध्यक्ष गणेश वोरेकर आदि मौजूद थे।

मंत्रालय में चेहरे की पहचान प्रणाली बंद कर आम जनता को प्रवेश दिया जाए

विजय वडेटीवार की मांग

मुंबई (विशेष प्रतिनिधि): मंत्रालय में प्रवेश के लिए लागू की गई चेहरा पहचान प्रणाली की वजह से आम जनता को परेशानी हो रही है। इसलिए इस प्रणाली को तुरंत बंद किया जाए, ऐसी मांग कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेटीवार ने की है।

अगर तालुका या जिला स्तर पर समस्याओं का समाधान नहीं होता, तो आम जनता अपने मुद्दे लेकर मंत्रियों और सचिवों से मिलने मंत्रालय आती है। लेकिन महायुती सरकार को जनता से डर क्यों लग रहा है? मंत्रियों और सत्ता पक्ष के विधायकों के करीबी ठेकेदारों और दलालों को मंत्रालय में आसानी से प्रवेश मिल जाता है, लेकिन किसानों, मजदूरों और आम जनता को प्रवेश से रोका जा रहा है। यह अन्यायपूर्ण व्यवस्था तुरंत बंद की जानी चाहिए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान विजय वडेटीवार ने कहा,

एक तरफ धान और सोयाबीन किसानों को अब तक पैसे नहीं मिले। किसानों की टपक (ड्रिप) सिंचाई की सब्सिडी बकाया है। मनरेगा मजदूरों को पिछले छह महीने से मजदूरी नहीं दी गई, जिसकी वजह से गढ़चिरोली में एक मजदूर



ने आत्महत्या कर ली। ओबीसी छात्रों को भी भत्ते नहीं मिले, उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार पूरी तरह कंगाल हो चुकी है, इसलिए हर वर्ग के साथ अन्याय किया जा रहा है। राज्य के इन गंभीर मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए सरकार के मंत्रियों में मतभेद और विवादों का माहौल तैयार किया जा रहा है, ऐसा आरोप भी वडेटीवार ने लगाया।

जामनेर में होगा ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय कुश्ती दंगल!

१६ फरवरी को फ्रांस, मोल्दोवा, उज्बेकिस्तान और रोमानिया के पहलवान अखाड़े में उतरेंगे

मुंबई (विशेष संवाददाता): जलागांव जिले का जामनेर कस्बा इतिहास रचने के लिए तैयार है। १६ फरवरी को यहां 'नमो कुश्ती महाकुंभ-२' के साथ 'देवाभाऊ केसरी' ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय कुश्ती दंगल का आयोजन किया जा रहा है। स्वस्थ शरीर, श्रेष्ठ खेल इस संदेश को बढ़ावा देते हुए इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य भारतीय महिला

कुश्ती को प्रोत्साहन देना है। इस दंगल में भारत, फ्रांस, मोल्दोवा, उज्बेकिस्तान, रोमानिया और एस्टोनिया के विश्व चैंपियन, ओलंपियन, हिंद केसरी, स्लम-ए-हिंद, भारत केसरी, महाराष्ट्र केसरी और उप-महाराष्ट्र केसरी जैसे नामी पहलवान हिस्सा लेंगे। यह आयोजन मिट्टी की कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित

होगा।

महाराष्ट्र में जबरदस्त उत्साह! इस ऐतिहासिक आयोजन के बारे में जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन, जो इस प्रतियोगिता के मुख्य आयोजक हैं, उन्होंने कहा कि इस आयोजन को लेकर पूरे महाराष्ट्र में जबरदस्त उत्साह है।

इस कुश्ती दंगल की वजह से जामनेर को अंतरराष्ट्रीय कुश्ती नक्शे

पर एक खास पहचान मिलेगी। इस अवसर पर उत्तर महाराष्ट्र में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल संकुल की भी घोषणा की जाएगी, जिससे सामान्य परिवारों से आने वाले खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। कुश्ती प्रेमियों के लिए यह एक शानदार अवसर होगा, जहां उन्हें विश्वस्तरीय पहलवानों को एक ही मंच पर देखने का सुनहरा मौका मिलेगा। यह प्रतियोगिता रविवार, १६ फरवरी को सुबह ११ बजे से शाम ८ बजे तक आयोजित की जाएगी।

सरकार किसानों से किया वादा पूरा करे-नाना पटोले

जमीर काजी। मुंबई। नाना पटोले ने आगे कहा कि भाजपा-युती सरकार ने चुनाव के दौरान ६,००० रुपये प्रति किंटल का भाव देने का वादा किया था, लेकिन अब किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल रहा। सरकार ने सोयाबीन की खरीद प्रक्रिया में भारी लापरवाही बरती है, जिससे लाखों किंटल सोयाबीन किसानों के घरों में पड़ा हुआ है और वे इसे औने-पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं।

सरकारी खरीद केंद्रों की कमी से बढ़ी पटोले ने कहा कि अगर सरकार खरीद

केंद्रों की संख्या बढ़ाती और किसानों की फसल समय पर खरीदती, तो यह समस्या उत्पन्न नहीं होती। लेकिन अब स्थिति यह है कि खरीद केंद्रों पर अव्यवस्था और भीड़ के कारण किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। अब जब ६ फरवरी तक का समय दिया गया है, फिर भी लाखों किंटल सोयाबीन की खरीद नहीं हो पाएगी। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह इस समयसीमा को बढ़ाए और यह सुनिश्चित करे कि हर किसान की फसल खरीदी जाए। सरकार की नीतियों से किसान निराश

पटोले ने कहा कि राज्य में सोयाबीन उत्पादक किसानों की हालत बहुत खराब हो गई है। खुला बाजार और बाजार समितियों में किसानों को बहुत कम दाम मिल रहे हैं। सरकारी खरीद केंद्रों पर अव्यवस्था फैली हुई है। मौजूदा सरकारी नीतियों की वजह से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने सरकार से तुरंत हस्तक्षेप करने और किसानों को उनका उचित हक दिलाने की मांग की। अगर सरकार ने जल्द निर्णय नहीं लिया, तो कांग्रेस किसानों के हक के लिए सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी, ऐसा स्पष्ट इशारा भी नाना पटोले ने दिया।



केंद्रीय बजट २०२५-२६ में कई अवसर गंवा दिए गए: जमाअत-ए-इस्लामी हिंद

नई दिल्ली, ०५फरवरी: केंद्रीय बजट २०२५-२६ पर टिप्पणी करते हुए जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के अमीर (अध्यक्ष) सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने कहा है कि इसमें कई अवसर गंवा दिए गए हैं।

मीडिया को जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट २०२५-२६ में आयकर में कटौती, छूट की सीमा को बढ़ाकर १२ लाख रुपये करने और मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए स्लैब को समायोजित करने जैसे कई सकारात्मक पहलुओं की हम सराहना करते हैं। इससे करदाताओं के हाथ में अधिक व्यय योग्य आय बचेगी तथा उपभोग एवं विकास को बढ़ावा मिलेगा। दूसरी सकारात्मक बात यह है कि १ लाख करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान के बावजूद, बजट में राजकोषीय विवेक बनाए रखा गया तथा राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के ४.४% तक सीमित रखा गया। इससे यह सुनिश्चित होगा कि हमारा उधार नियंत्रित रहेगा। इसके अलावा व्यावसायिक विनियमनों को सरल बनाने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा विनियामक सुधारों को आगे बढ़ाने से व्यवसाय को आसान बनाने में मदद मिलेगी तथा निवेश और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

जमाअत के अध्यक्ष ने आगे कहा, हम कई मामलों में इस बजट से निराश हैं। युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी, प्रति व्यक्ति कम जीडीपी और कृषि विकास के साथ गंभीर आजीविका संकट के आधार पर वित्त मंत्री के लिए बजट में आमूलचूल नीतिगत बदलाव करने का एक अच्छा अवसर था कि असमानता, बेरोजगारी और उपेक्षित वर्गों की समस्या को दूर करने के लिए पुनर्वितरण न्याय,

समान विकास और प्रभावी शासन को प्राथमिकता दी जा सके। जमाअत-ए-इस्लामी हिंद ने बजट से पहले वित्त मंत्रालय को अपने सुझाव सौंपे थे जिसमें व्यापार वृद्धि और कर प्रोत्साहन पर केंद्रित 'आपूर्ति' की रणनीति से हटकर नागरिकों की क्रय शक्ति में वृद्धि, उपभोग को प्रोत्साहन और कल्याणकारी कार्यक्रमों को बढ़ाने के उद्देश्य से 'मांग' की रणनीति अपनाने की जोरदार वकालत की गई थी। दुर्भाग्य से, जब हमने बजट २०२५-२६ का अध्ययन किया तो हमें लगा कि हमारे अधिकांश सुझावों को नजरअंदाज कर दिया गया। ऐसा लगता है कि बजट में कई अवसर चूक गए। केंद्रीय बजट २०२५-२६ को स्वाभाविक तौर से विस्तारवादी होना चाहिए था।लेकिन इसके विपरीत

कुल व्यय में लगभग एक लाख करोड़ की कमी कर दी गई है। इसका सामाजिक व्यय पर प्रभाव पड़ना निश्चित है तथा गरीबों की दुर्दशा और भी अधिक बढ़ जाएगी। सैयद सआदतुल्लाह ने कहा, हमने मनरेगा में कटौती को वापस लेने, शहरी रोजगार योजना शुरू करने, स्वास्थ्य सेवा पर खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के ४% तक बढ़ाने और सकल घरेलू उत्पाद के ६% आवंटन के साथ एक व्यापक शिक्षा मिशन शुरू करने की मांग की थी। इन सभी मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसके अलावा, बजट में अल्पसंख्यकों के उत्थान, एससी/एसटी सशक्तिकरण या कृषि ऋण राहत पर स्पष्ट रूप से ध्यान नहीं दिया गया है जिससे सामाजिक न्याय और समान विकास के प्रमुख मुद्दे अनसुलझे रह गए हैं। हमने राजस्व के मामलों में आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी की अधिकतम सीमा ५% रखने, विलासिता कर लगाने, बड़ी कंपनियों पर अप्रत्याशित लाभ कर लगाने और

केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाकर ५०% करने का सुझाव दिया था। लेकिन, बजट इन महत्वपूर्ण उपायों पर चुप है। इसी प्रकार, विदेशी प्रौद्योगिकी कंपनियों पर डिजिटल कर, कर-मुक्त अवसंरचना बांड, तथा प्रभावी मानकों के साथ मजबूत सीएसआर मानदंडों को शामिल नहीं किया गया। इन सुधारों का अभाव से असमानता को दूर करने, कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए राजस्व उत्पन्न करने तथा वित्तीय न्याय सुनिश्चित करने के अवसर समाप्त हो जाएंगे। हमारा दृढ़ मत है कि सरकार को एक प्रगतिशील राजस्व नीति अपनाने की आवश्यकता है जो आम नागरिक को प्राथमिकता दे तथा समतामूलक विकास का समर्थन करे। वर्तमान बजट पर अपनी प्रतिक्रिया के अंत में उन्होंने कहा, जैसा कि बजट २०२५-२६ के अवलोकन से पता चलता है, व्यय का बड़ा हिस्सा (२०%) ऋण पर ब्याज भुगतान की ओर जाता है। यह हमारे गैर-उत्पादक व्यय का एक बड़ा हिस्सा है जिसका उपयोग हम लोगों के कल्याण के लिए कर सकते थे। ऋण-जाल में फंसे से बचने के लिए हमें इक्विटी-आधारित वित्त मॉडल और ब्याज मुक्त अर्थव्यवस्था की ओर साहसिक कदम उठाना होगा। पारंपरिक बैंकों में इक्विटी-आधारित ब्याज-मुक्त बैंकिंग सुविधा को शामिल करके हम इस दिशा में शुरुआत कर सकते हैं। हमारी ओर से वित्त मंत्रालय को भी यह सुझाव दिया गया। यह एक अभिनव दृष्टिकोण होगा और हमें अपने राजनीतिक विचारों को गंभीर आर्थिक और ऋण-संबंधी चुनौतियों के लिए समय-परीक्षित समाधान तलाशने से नहीं रोकना चाहिए। हम आशा करते हैं कि सरकार पक्षपातपूर्ण और वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठेगी तथा बजट को आर्थिक नीति में वास्तविक परिवर्तन के साधन के रूप में रखेगी, जिससे देश के सभी नागरिकों को लाभ पहुंचे।



आज बीड में रेलवे विभाग के वरिष्ठ अधिकारी आए थे। उन्हें बीड के रेलवे स्टेशन का नाम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के नाम पर रखने की मांग को लेकर सभी भीमसैनिकों की ओर से एक ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर ज्ञापन सौंपते समय भीम योद्धा अनुरथ वीर (फौजी), बाळासाहेब मोरे, संदीप जाधव, राज कांबळे, यशपाल, अमोल अहिरे सहित अनेक भीमसैनिक उपस्थित थे।

SAPNA TRAVELS

- ➡ AC Sleeper
- ➡ Free Wifi
- ➡ Free Water bottle
- ➡ Mobile Charging
- ➡ CCTV Camera & GPS
- ➡ Clean & Comfortable bed

Heavy Parcel Booking

9960828578 / 9156333999

Beed Office

9075868000
7058575575

Online Booking

www.redbus.in

Beed to Mumbai (panvel-sion-borivali)

Beed to Pune (bhosari-nigdi)

Shivaji Chowk, Near Mahindra showroom, Beed-431122

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com